

बिहार के झटके के बाद इंडिया गठबंधन में बेचैनी सी है राहुल गांधी के विपक्ष के नेता पद के बारे में

कांग्रेस ने संसद के आगामी सत्र से पहले विपक्ष की बैठक बुलाने का प्रयास किया था वोट चोरी के मुद्दे पर, पर यह प्रयास विफल हुआ

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19 नवम्बर। बिहार में मिली करारी हार ने इंडिया ब्लॉक के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है, क्योंकि राज्य-आधारित दल अब राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता मानने में असहज दिखाई दे रहे हैं।
लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटों तक सीमित रखने के बाद, विपक्ष, खासकर कांग्रेस, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हार के बाद, अपना “मोमेंटम” (अपनी गति) बनाए नहीं रख सका। झारखंड में कुछ मजबूती दिखी, जहाँ इंडिया ब्लॉक ने विधानसभा की 81 में से 56 सीटें जीतीं। जम्मू-कश्मीर में भी विपक्षी गठबंधन ने 90 में से 49 सीटें जीतीं। लेकिन बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद माना जा रहा है कि भाजपा ने 2024 की हार की भरपाई कर ली है।
इंडिया ब्लॉक के भीतर बेचैनी साफ दिख रही है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने

- प्रमुख विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस व सपा ने इस प्रयास से दूरी बनाने का मन बनाया।
- महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी), जो कांग्रेस नेतृत्व वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कांग्रेस के साथ पार्टनर थी, ने भी कांग्रेस का मखौल उड़ाया कि कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद पाकर इतरा तो रही है, पर, उसका जमीनी प्रदर्शन काफ़ी लड़खड़ा रहा है।
- आगामी असेंबली चुनाव में क्षेत्रीय दल कांग्रेस को ज्यादा भाव नहीं देंगे, ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को बंगाल के चुनावों में ज्यादा एकांमोडेट करने के मूड में नहीं है।
- तमिलनाडु में द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन में भी अब उतनी गर्मी नहीं है।
- द्रमुक, कांग्रेस से अप्रसन्न है, क्योंकि कांग्रेस सिनेस्टार व राजनीतिज्ञ विजय से नज़दीकी दिखाती रही है। अरविंद केजरीवाल पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे गठबंधन से नाता तोड़ रहे हैं तथा अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाना ही सार्थक समझ रहे हैं।

विपक्षी दलों की बैठक बुलाकर “वोट चोरी” मुद्दे को संसद में उठाने की कोशिश की। लेकिन तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित, गठबंधन के प्रमुख पार्टनरों ने इस पहल में खास रुचि नहीं दिखाई है।
महाराष्ट्र की घटनाएँ बहुत कुछ सीख देती नजर आ रही हैं। बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने की कांग्रेस की घोषणा के बाद, शिवसेना (यूबीटी), जो पहले महा विकास अघाड़ी सरकार का हिस्सा थी, ने कांग्रेस का मज़ाक उड़ाया। पार्टी के मुखपत्र “सामना” के संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह अपनी “राष्ट्रीय पार्टी” की पहचान का ढोल पीटकर अपना महत्व साबित करना चाहती है, जबकि उसका प्रदर्शन लगातार कमजोर होता जा रहा है।
अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों का साथ मिलना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ चुनाव अगले साल की शुरुआत (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महिला सब इन्सपैक्टर सवा लाख रुपए की रिश्तत लेते गिरफ्तार

जयपुर, 19 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय की जयपुर नगर तृतीय टीम ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के गांधीनगर थाने की महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा को सवा लाख रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर तृतीय टीम को परिवादी ने शिकायत दी कि पुलिस थाना

- **गांधी नगर पुलिस थाने में तैनात राजकुमारी जुनेजा को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा।**

गांधीनगर में दर्ज प्रकरण में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने एवं मुकदमे में एफआर लगाने की एवज में महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा दो लाख रुपये की रिश्तत मांग रही है।
इस पर एसीबी जयपुर नगर तृतीय टीम के पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार स्वामी के नेतृत्व में ट्रेप की कार्रवाई करते हुए महिला पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) राजकुमारी जुनेजा को सवा लाख रुपये की रिश्तत लेते गिरफ्तार किया है।

राजस्थान वि.वि. में कुलपति की नियुक्ति पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

जयपुर, 19 नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति पद पर प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नियुक्ति देने से जुड़े मामले में राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रोफेसर अल्पना कटेजा को नोटिस भेज कर जवाब तलब किया है। जस्टिस अशोक कुमार जैन की

- **प्रो. अल्पना कटेजा पर आरोप है कि आवंटन करते समय उन्होंने लंबित अपराधिक प्रकरण को छुपाया।**

एकलपीठ ने ये आदेश प्रोफेसर महिपाल सिहाग की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मामले में दायर स्टे एप्लिकेशन पर आदेश जारी करने से पहले प्रोफेसर अल्पना को सुनवाई का मौका दिया जाना उचित रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई 21 (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रवासी राजस्थानी विभाग बनेगा, ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर स्थापित होंगे

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए

जयपुर, 19 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही, राजस्थान ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर पॉलिसी के अनुमोदन तथा आरबीयूपएनएल व सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन सहित कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगामा पटेल ने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आज मंत्रिमंडल ने ‘राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग’ के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

- **प्रवासी राजस्थान विभाग से विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान स्थापित होगा व लोकप्रिय बनेगा।**
- **ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर नीति के तहत 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनसे 1.50 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे।**

यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों और राज्य सरकार के बीच संवाद और सहयोग के लिए एक संशक्त मंच उपलब्ध करवाएगा, जिससे प्रवासियों का अपनी मातृभूमि से जुड़ाव और मजबूत होगा। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से यह विभाग विश्व पटल पर ब्रांड राजस्थान को प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने बताया कि यह विभाग प्रवासी राजस्थानियों को राज्य सरकार की योजनाओं से

लाभान्वित करने और उनके विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए नीतिगत ढांचा उपलब्ध करवाएगा। प्रवासी राजस्थानी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल का संचालन भी इस विभाग द्वारा किया जाएगा।
कर्नल राठौड़ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्लोबल केपबिलिटी सेंटर पॉलिसी-2025 का अनुमोदन किया है। यह नीति वर्ष 2030 तक राजस्थान में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित करने, 1.5

लाख रोजगार के अवसर सृजित करने के साथ ही देश के 100 अरब डॉलर के जीसीसी बाजार में महत्वपूर्ण योगदान देने के लक्ष्य पर आधारित है। राज्य सरकार इस नीति के माध्यम से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे शहरों को जीसीसी हब के रूप में विकसित करेगी।
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (आरबीयूपएनएल) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के बीच जॉइंट वेंचर(जे.वी.) कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह जेवी खदान स्थल पर 9,600 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएँ स्थापित करेगी।

मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए द.अफ्रिका जायेंगे

नयी दिल्ली 19 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी-20 नेताओं के 20वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की तीन दिन की यात्रा पर जाएंगे।

यह ग्लोबल साउथ में 22-23 नवंबर को आयोजित होने वाला लगातार चौथा जी- 20 शिखर

- **तीन दिन की यात्रा पर वे शुक्रवार को रवाना होंगे।**

सम्मेलन होगा। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमन्त्री –20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी तीन सत्रों में संबोधन की उम्मीद है। जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री द्वारा जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे।

यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर 33 लाख की ठगी

आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया , लेकिन वहां पर बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली

श्रीगंगानगर, (निसं)। यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक से पैसे ले लिए और विदेश भेज दिया। लेकिन वहां पर उसे बताई गई नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिली। आरोपी अब पैसे लौटाने से मना कर रहे हैं। मामला श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को दी रिपोर्ट में राजकुमार (45) निवासी साधुवाली (श्रीगंगानगर) में बताया कि उसका बेटा सागर 12वीं पास कर यूके में पढ़ाई करना चाहता था। मई 2025 में शिकायतकर्ता व उसके बेटे की जान-पहचान साधुवाली के अनुराग

नाम के शख्स से हुई। अनुराग ने 22 लाख में स्टडी वीजा और यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने का झांसा दिया। जब राजकुमार ने पैसे नहीं होने की बात कही तो अनुराग ने उसे स्टडी लोन दिलवाने की बात कही। जिसके बाद आरोपियों ने राजकुमार के बेटे का स्टडी लोन अयुव करवा दिया। कुछ दिनों बाद युवक के अकाउंट में 33.87 लाख रुपए क्रेडिट हो गए।

इसके बाद ठगों ने बाप-बेटे की चेकबुक, एटीएम कार्ड और पासवर्ड व खाली स्टाम्प अपने पास रख लिए। 24 से 28 जुलाई 2025 के बीच आरोपी अनुराग, नवल और साहिल ने युवक के अकाउंट से अलग-अलग बैंक अकाउंट में 33 लाख से ज्यादा

रुपए ट्रांसफर कर लिए। जिसके बाद आरोपियों ने परिवार को बताया गया कि ब्रिस्टल (यूके) की यूनिवर्सिटी में सागर का एडमिशन हो गया। सागर की फीस जमा हो गई और वीजा आ गया।

तीन अगस्त को सागर को दिल्ली से यूके भेज दिया गया। ब्रिस्टल पहुंचते ही सागर को पता चला कि जिस यूनिवर्सिटी का पता अनुराग ने दिया था, वहां ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है ही नहीं। जिसके बाद सागर ने पिता को फोन किया। राजकुमार जब अनुराग के इमीग्रेशन ऑफिस पहुंचे तो ठगों ने कहा कि उन्होंने ठगी की है और पहले भी ऐसे कई केस उनके खिलाफ हैं। आरोपियों ने चेकबुक-एटीएम कार्ड लौटाने से भी मना कर दिया। फिलहाल

रसद विभाग के सूत्र बताते हैं कि बड़ी मात्रा में सिलेंडर इकट्ठा होना तभी संभव है जब, गैस एजेंसियों से गलत डिलीवरी की मिलीभगत हो, डोमेस्टिक सिलेंडरों का कर्मशियल उपयोग हो, कई फर्जी-दोहराए गए उपभोक्ता आईडी का इस्तेमाल हो या फिर यह सब स्थानीय स्तर पर अथवा रीफिलिंग के लिए किया जाए। मुद्दा यह भी उठता है कि क्या रसद विभाग हर कार्रवाई के बाद संबंधित गैस एजेंसियों की बुकिंग-डिलीवरी पैटर्न की जांच करता है क्योंकि जब तक कम्प्लाय चैन में संच का पता नहीं लगेगा, दुकानों पर छापे केवल बाहरी परतें ही हटाएंगे, जड़ नहीं।

भरतपुर में आवासहीनों ने किया प्रदर्शन



आवासहीनों ने नगर निगम भरतपुर के गेट पर प्रदर्शन किया।

भरतपुर, (निसं)। आवासहीनों को आवास या जमीन दिलाये जाने के सिलसिले में आवासहीन जन संघर्ष समिति भरतपुर-राजस्थान के बैनर तले नगर निगम भरतपुर के गेट पर लगभग 300 महिलाओं व पुरुषों ने घरना देकर नारे लगाये। इसके बाद लगभग बीसियों प्रतिनिधियों ने अधिकारियों को ज्ञापन देते समय स्पष्ट तौर से चेतावनी दी कि यदि अखिलम्ब हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर निगम पर लगातार और सहपरिवार पड़ाव डाला जायेगा और आन्दोलन को निरन्तर तेज किया जायेगा, जिसकी सारी जवाबदेही

निगम प्रशासन की होगी।

इस मौके पर कामरेड नथूलाल ने कहा कि सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना होते हुए भी गरीब आवासहीनों को इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में संघर्ष करना पड़ रहा है। इस घरना आन्दोलन का नेतृत्व कामरेड नथूलाल, यादराम प्रजापत अध्यक्ष, कलुआ खान महासचिव, अशोक कपूर, रम्यो सिंह हवलदार, अशोक कुमार जघीना, डॉ. नवलिका, एड. रूचि गर्ग, सुमन योगी, ओमपवती, सुनीता, रगुड़ी, पूनम, उमेश नायक आदि ने किया।



जिला प्रशासन द्वारा गैस रिसाव की परिस्थितियों से निपटने के लिए माँक डील का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

जानकारी दी गई। इस दौरान जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव रवीन्द्र, एडीएम द्वितीय योगेश शरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय काम्बले शरण गोपीनाथ, नगर निगम के आयुक्त सोहन सिंह नरुका, उपखण्ड अधिकारी

अलवर माधव भारद्वाज, डिप्टी सीएमएचओ डॉ. महेश बैरवा, जीएम डीआईसी एम.आर. मीणा, पीडब्ल्यूडी की अधिष्ठासी अभियन्ता अल्का व्यास, एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट संजय गुर्जर सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

बताया कि वह अपने परिवार के साथ खाटूस्थामजी (सीकर) के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। इस दौरान पीछे से उनके बंद पड़े मकान में चोरी हो गई। चोर मकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे और लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवरों और अलमारी में रखे पांच लाख कैश चोरी कर भाग गए। वह जब (मकान मालिक और परिवार) अपने घर वापस लौटे तो देखा कि मकान में टूटे हुए ताले लटके रहे थे और मकान में चोरी हो चुकी थी। अंदर सामान बिखरा हुआ था। जिसके बाद मकान मालिक ने पुलिस को रिपोर्ट दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका-सुआयना किया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

गेहूं से भरा ट्रक सड़क में धंसा

भीलवाड़ा, (निसं)। नगर निगम की ओर से सीवरेज का कितना घटिया स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली। पुलिस लाइन क्षेत्र में एक ट्रक गेहूं से भरकर जा रहा था। तभी सपाट सड़क में धंस गया। एक बारगी तो ट्रक ड्राइवर भी हैरान रह गया। वह नीचे उतरा दूसरे लोगों से मदद की गुहार लगाई। लेकिन

■ **लोगों ने आरोप ने लगाया कि सीवरेज का निर्माण कार्य घटिया स्तर का किया जा रहा है**

जब ट्रक की हालत देखी तो क्रेन ही बुलानी पड़ी। पहले पिकअप में गेहूं की बोराियां खाली कराई गईं, बाद में क्रेन की मदद से निकाला जा सका।

लोगों ने आरोप ने लगाया कि पटरी पार सीवरेज का निर्माण कार्य

राजस्थान हाईकोर्ट : सर्विस बुक की अनुपलब्धता पेंशन में बाधक नहीं

■ **सफाईकर्मों के पद पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली में कार्यरत कर्मचारी की रिट याचिका स्वीकार**

इस पर उसने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक विधिक नोटिस प्रेषित किया। विधिक नोटिस के जवाब में विभाग 01 मार्च 2019 को पत्र ड्राए उसे यह सूचित किया गया कि उसकी सर्विस बुक उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे पेंशन व पेंशन संबंधी लाभ प्रदान नहीं किये जा सके।

विभाग के इस कृत्य से व्यथित होकर रमेश ने अपने अधिवक्ता प्रमेन्द्र बोहरा के माध्यम से एक रिट याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क था कि किसी भी कर्मचारी की सर्विस बुक का

उड़ान स्कूल का नया भवन शहर को समर्पित

नसीराबाद, (निसं)। नसीराबाद छावनी क्षेत्र में विशेष बच्चों के लिए उम्मीदों का नया केंद्र बन चुका ‘उड़ान स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन’ बुधवार को अपने आधुनिक स्वरूप में शहर को समर्पित किया गया। जीपीओद्वार कार्य पूरा होने के बाद आरंभजित इस भव्य उद्घाटन समारोह में छावनी परिषद अध्यक्ष ब्रिगेडियर हरिश कुमार और सौनिका ने विद्यालय का लोकार्पण किया।

समारोह में मुख्य अधिष्ठासी अधिकारी डॉ. नीतिश गुप्ता, एम एच कमांडर आर के यादव और मनीनोत सदस्य सुशील कुमार आदि उपस्थित रहे। अनेक गर्मियां अधिकारी, अभिभावक और स्थानीय नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान चलाए गए वीडियो में उड़ान स्कूल की पुरानी और नई तस्वीरों साथ दिखाई गई। पुरानी स्थिति देखकर यह महसूस किया गया कि पहले भवन इतना जर्जर था कि अंदर प्रवेश करने समय भी डर लगता था। दीवारों की टूट-फूट, फर्श की जर्जरता और सीमित सुविधाओं ने वर्षों तक बच्चों के विकास में बाधा उत्पन्न की थी, लेकिन अब वही भवन आधुनिक, सुरक्षित और आकर्षक मॉडल स्कूल का रूप लेकर खड़ा है।

प्रदेश कांसिंस कमेट्री के सचिव सुनील लारा के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता स्कूल के मुखेद्धार पर पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ

नापासर में इंडस्ट्रियल ऑयल फैक्टरी की जांच पूरी

■ **फैक्टरी में इंडस्ट्रीयल ऑयल को बाँयोडीजल बताकर बेचे जाने के मामले में रसद विभाग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ**

■ **जांच में सामने आया है कि परिसर में भूमिगत टैंकों से लेकर प्लास्टिक टंकियों तक में करीब 3 लाख 14 हजार लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था**

■ **जांच के दौरान फर्म न तो वैध एंड कर सकी और न ही उत्पाद के भंडारण, परिवहन या बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड**

छापा मारकर गोरखधंधे का खुलासा किया था। जांच से पता चलता है कि यह कोई एक-दो टैंकर का खेल नहीं था। 3 लाख लीटर से अधिक स्टॉक का मतलब है कि सप्लाई चेन बेहद विस्तृत है। छोटे बान्हों में लोडिंग यानी बाजार में अवैध तरीके से यह इंडस्ट्रीयल ऑयल बाँयोडीजल के नाम पर बड़ी मात्रा में बेचा जा रहा था। मंत्रों के छोपे के बाद भी किसी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई न होना इस नेटवर्क की सुरक्षा छतरी की ओर इशारा करता है।

जानकारी के अनुसार कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 6 नवंबर की रात भारत माला रोड पर एक युवक को एक गाड़ी में संदिग्ध बाँयोडीजल भरते देखा। इसके बाद मंत्री मीणा उस युवक सहित नापासर स्थित कनकश्री फैक्टरी पहुंचे। मौके पर चालक ने कहा हम पुलिस को बंधी देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता। मंत्री मौके पर पहुंचे तो वहां छोटी गाड़ियों में फ्यूल भराई जारी मिली। उसी रात फैक्टरी सील, फिर रसद विभाग ने विस्तृत जांच शुरू की।



भीलवाड़ा में गेहूं से भरा ट्रक सपाट सड़क में धंस गया।

घटिया स्तर का किया जा रहा है लेकिन कोई भी बोलने वाला नहीं है। हालात ये हैं कि इन वार्डों के पार्षद भी नगर निगम की ओर से कराए जा रहे कार्यों का विरोध नहीं करते हैं, जबकि पहले रडिप की ओर से कराए जा रहे सीवरेज कार्य के विरोध के लिए

एकमत हो रखे थे। पार्षद हो या प्रशासनिक अधिकारी या फिर समाजसेवी सभी उसके विरोध में उतरे हुए थे। स्थानीय लोगों ने कहा कि एक बार आप इन वार्डों में घूम कर देखिए, आपको पता चलेगा कितने मुश्किल हालात में रहने को मजबूर है।

एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया मथानिया स्थित उम्मेद नगर नट बस्ती का रहने वाला 22 वर्षीय कमलेश पुत्र प्रेमराम नट का शव आज सुबह उसके घर के सामने रहने वाले पड़ौसी के यहां पर नजदीक में मिला। सुबह साढ़े सात बजे पुलिस को सूचना मिली और उसकी हत्या किए जाने की जानकारी दी गई।

रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई

सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े मामलों में फैसला सुनाया

श्रीगंगानगर, (निसं)। जोधपुर की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने श्रीगंगानगर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुए तीन बड़े भ्रष्टाचार के मामलों में सनसनीखेज फैसला सुनाया। रिश्वत मामले में तीन एमईएस अफसरों को सजा सुनाई।

ठेकेदार दीपक अनेजा की शिकायत पर 12 अप्रैल 2016 को सीबीआई ने रिश्वत देते तीन अधिकारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। साढ़े नौ साल बाद आए इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार अब देश की रीढ़ तोड़ रहा है। इस केस के करीब साढ़े नौ साल बाद 18 नवंबर को सुनाए गए फैसले में अकाउंट्स ऑफिसर हरिसिंह नागले और अनिल बेदगिरी को दोषी करार देते हुए 4-4 साल की सजा सुनाई गई, जबकि राधेश्याम सोनी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की

धारा 7 में 3 साल की सजा सुनाई। वहीं, यूडीसी हेतराम और एन.एन. मोहंती को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। तीनों मामलों में सीबीआई की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक भगवानसिंह भंवरिया ने पैरवी की, जबकि अभियुक्तों की ओर से एडवोकेट जे.के. चांडा व अन्य ने पैरवी की।

न्यायालय ने अपने फैसले में भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक विशाल समस्या बन गई है और यह सर्वत्र फैल गई है। किसी भी सार्वजनिक गतिविधि का कोई क्षेत्र भ्रष्टाचार की दुर्गंध से अप्रभावित नहीं रहा है। इसका गहरा और व्यापक प्रभाव पूरे देश के कामकाज पर पड़ता है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार राष्ट्र-निर्माण गतिविधियों में बाधा डालता है और सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

गैस रिसाव की परिस्थितियों से निपटने के लिए माँक डील

अलवर, (निसं)। राजस्थान आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत गैस रिसाव (केमिकल डिजास्टर) की परिस्थितियों से निपटने के लिए एगुरुवार को एमआईए स्थित लॉड्रूस क्लोरो अल्कली लिमिटेड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राहत एवं बचाव से जुड़े अन्य सुरक्षाकर्मियों का माँक डील का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर एवं इंसीडेंट मजिस्ट्रेट बीना महावर के निर्देशन में माँक डील के तहत किए गए बचाव एवं राहत कार्य संपादित किए गए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर ने बताया कि जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में आपातकालीन परिस्थितियों में गैस रिसाव की समस्या से निपटने के लिए माँक डील का आयोजन किया गया जिसके तहत एमआईए स्थित लॉड्रूस क्लोरो एलकलीज कम्पनी लि. में क्लोरीन स्टोरेज टैंक से गैस के रिसाव की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कम्पनी के 32 कार्मिक बेहोश हो गए। सूचना प्राप्त होते ही कंट्रोल रूम से संबंधित राहत

दलों एवं अधिकारी को त्वरित सूचना प्रसारित की गई, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस, अग्निशमन दल, चिकित्सा दल, सिविल डिफेन्स, स्काउट व गाइड, एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के दलों ने तुरन्त मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य प्रारम्भ किया। गैस लीकेज के दौरान काम में आने वाले मास्क एवं विशेष ड्रेस पहनकर राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया गया। माँक डील के दौरान एनडीआरएफ 6वीं बटालियन गुप्तरात से आए ऑफिसर इं चार्ज डॉ. परमिंदर सिंह ने गैस रिसाव से होने वाली क्षति के तहत आपातकालीन अलार्म का उपयोग, राहत कार्यों का प्रदर्शन एवं रखी जाने वाली विशेष सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सीबीआरएन से बचाव संबंधित उपकरणों एवं भिन्न-भिन्न प्रकार के तरीकों एनसीएएल में फंस रहे लोगों को बचाने का प्रदर्शन किया गया जिसमें लीकेज अरेस्ट करने, रेस्क्यू करने विभिन्न तकनीक तथा उपकरणों आदि से निकलने की तकनीकी



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त के हस्तान्तरण कार्यक्रम को संबोधित किया। समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल व सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार भी शामिल हुए ।

किसानों को लाभांवित करने में राजस्थान देश में पाँचवे स्थान पर- भजनलाल

पीएम किसान सम्मान निधि पर मुख्यमंत्री ने राज्यस्तरीय कार्यक्रम को संबोधित किया

जयपुर, 19 नवम्बर (कासे)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सोच देश के किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के विकास से जुड़ी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों के अनुरूप अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के विकास तथा हर जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाकर उसके जीवन स्तर को उठाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में पीएम किसान सम्मान निधि की 21 वीं किस्त

- प्रधानमंत्री मोदी ने कोयम्बटूर में किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त हस्तांतरित की, मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में वीसी के माध्यम से जुड़े।**

के हस्तान्तरण कार्यक्रम से वीसी के माध्यम से जुड़े। जयपुर के दुर्गापुरा के राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अब तक 20 किस्त जारी हुई हैं, जिससे राजस्थान के किसानों के खातों में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की

जा चुकी है। 21 वीं किस्त में लगभग 1400 करोड़ की राशि किसानों के खातों में जमा करने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभांवित किसानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में पांचवां स्थान है।

उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार तीन हजार रुपये की राशि अलग से दे रही है। इसके अलावा, किसानों की बिजली के बिलों में 41 हजार करोड़

रुपये से अधिक का अनुदान दिया गया है।

समारोह में कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीना ने कहा कि कृषि और सहकारिता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने कहा कि किसान हमारे समाज और अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं।

इस दौरान सहकारिता से संबंधित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, शासन सचिव कृषि राजन विशाल सहित, संबंधित विभाग के उच्चाधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे।

नीतीश ने अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
शासन की अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था।

जनता का विश्वास वापस पाने और भाजपा के साथ नई सत्ता-साझेदारी की जटिलताओं को संभालने की दोहरी चुनौती के बीच, नीतीश कुमार ने यह निर्णायक कदम उठाया है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने नए कार्यकाल की शुरुआत इस साफ संदेश के साथ करना चाहते थे कि कैबिनेट में जगह वफादारी से नहीं, बल्कि ईमानदारी से तय होगी।

यह कदम भाजपा पर भी हल्का-सा दबाव बनाता है, जिसके डिस्टी सीएम उम्मीदवार अभी भी अप्रिय

एकल पट्टा क्लोजर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हाईकोर्ट ने भी आगामी जांच के लिए कहा है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने की मंजूरी दी जाए। इसके साथ ही, मामले में इन्टरवीन अशोक पाटक ने कोर्ट से प्रोटेस्ट पिटिशन पेश करने के लिए समय मांगा, जिस पर एसीबी कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है।

गौरतलब है कि तत्कालीन डीआईजी सवाई सिंह गोदारा ने तीसरी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर कहा था कि कोई मामला नहीं बनना पाया गया। वहीं, परिवारी रामशरण सिंह के

आरोपों से घिरे हुये हैं। भ्रष्टाचार-विरोधी समीक्षा एवं सहीशा की रेखांकित करने वाला नीतीश का यह फैसला आने वाले दिनों में गठबंधन की कार्यशैली और प्राथमिकताओं को प्रभावित कर सकता है।

अशोक चौधरी को हटाकर नीतीश कुमार ने अपने प्रशासन के लिए एक स्पष्ट रेखा खींच दी है, राजनीतिक जान-पहचान विश्वसनीयता के महत्व पर भारी नहीं पड़ेगी। जहाँ विपक्ष इसे मजबूरी में उठाया गया राजनीतिक कदम बता रहा है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन इसे बिहार में साफ और जवाबदेह शासन की दिशा में उठाया गया मजबूत कदम बता रहा है।

सोलह जजों, एक सौ तेइस रिटायर्ड ...

अधिवक्ता रहे संदेश खंडेलवाल ने बताया कि इस क्लोजर रिपोर्ट को परिव्रादी ने प्रोटेस्ट पिटिशन के जरिए चुनौती देते हुए मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया था।

इस प्रोटेस्ट पिटिशन पर भी सुनवाई होनी है। दरअसल हाईकोर्ट ने पूर्व यूडीएफ मंत्री शक्ति धारीवाल की याचिका पर एक नवंबर को सुनवाई करते हुए एसीबी की क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती देने वाली प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई का रास्ता साफ कर एसीबी को आगामी कार्रवाई की छूट दी थी।

मान्यता प्राप्त किये बिना ही अल फलाह ने 4 1 5 करोड़ रु.

की फीस वसूली साकेत अदालत ने सिद्दीकी को धनशोधन के मामले में 13 दिन की ईडी हिरासत में भेजा

नयी दिल्ली (19 नवंबर) दिल्ली की एक अदालत ने अल-फलाह विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के अध्यक्ष एवं कुलाधिपति जावद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी वाले मान्यता दावों से जुड़े घनशोधन मामले में 13 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। यह आदेश मंगलवार देर रात साकेत जिला न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान ने पारित किया।

ईडी ने 14 दिन की हिरासत की मांग करते हुए तर्क दिया था कि सिद्दीकी उस योजना के केंद्र में था जिसमें अल-फलाह विश्वविद्यालय और उसके संबद्ध संस्थानों ने कथित रूप से लगभग 415.10 करोड़ रुपये की अपराध आय अर्जित की थी। एजेंसी के अनुसार, यह राशि एनएएसी मान्यता और यूजीसी मान्यता के झूठे दावों के आधार पर छात्रों से एकत्रित की गई फीस है।

ईडी के अनुसार छात्रों से फीस की राशि एनएएसी मान्यता व यूजीसी मान्यता के झूठे दावे के आधार एकत्रित की गई।

ईडी ने तर्क दिया कि इन भ्रामक प्रथाओं का उपयोग छात्रों एवं अभिभावकों को बेईमानी से फीस का भुगतान करने हेतु प्रेरित करने के लिए किया गया, जिससे अत्यधिक अपराध आय अर्जित हुई। 2014-15 से 2024-25 तक आयकर रिटर्न के वित्तीय विश्लेषण से पता चला कि शैक्षणिक राजस्व में भारी वृद्धि हुई है, जिन वर्षों में संस्थान को मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी उन वर्षों के दौरान कुल 415.10 करोड़ रुपये को शैक्षणिक

केरल में एसआईआर की याचिकाओं की सुनवाई 21 को

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केरल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह को सुनवाई के लिए 21 नवंबर को सुचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

अधिवक्ता हारिस बीरन ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के समक्ष इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की ओर से दायर याचिका का हवाला दिया, जिसमें इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

बीरन ने दलील दी कि राज्य में चल रहे स्थानीय निकाय चुनावों के कारण एसआईआर को एक साथ कराना व्यावहारिक रूप से कठिन हो जाएगा।

अधिवक्ता सी.के. शशि ने केरल सरकार की याचिका का भी उल्लेख किया, जिसमें एसआईआर अधिसूचना को चुनौती नहीं दी गई है, बल्कि स्थानीय निकाय चुनाव समाप्त होने तक पुनरीक्षण प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग की गई है।

अनमोल बिश्नोई के दिल्ली पहुंचते ही एनआईए ने गिरफ्तार किया

उस पर सिद्धू मूसावाला व बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तथा सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले दर्ज हैं

नयी दिल्ली ,19 नवंबर। खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से प्रत्यापित कर दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर उतरते ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया।

अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था। वर्ष 2022 से फरार और अमेरिका में रह रहा अनमोल बिश्नोई जेल में बंद अपने भाई लॉरेंस बिश्नोई की अगुवाई वाले

पेपर लीक के मास्टर माइंड जगदीश विश्नोई की जमानत याचिका खारिज

हाई कोर्ट ने विश्नोई के साथ तीन अन्य आरोपियों को भी जमानत देने से इनकार किया

- आठ महीने पहले जगदीश विश्नोई को जैईएन-भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में जेल में बंद होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ पाया था।**

ने कहा कि जगदीश विश्नोई ही एसआई भर्ती, 2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। उसने ही गैंग बनाकर पेपर लीक किया और भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता को भंग किया। वहीं, राजीव बिश्नोई न केवल अभ्यर्थी है, बल्कि गैंग

हैडलर भी है। उसने ही पेपर को सांल करके आगे फैलाया था। वहीं कार्तिकेय शर्मा ने पेपर खरीदकर रिकू यादव को बेचा। आरोपियों ने मिलीभगत कर एसआई भर्ती का पेपर लीक किया। आरोपियों के खिलाफ अभियोजन के पास पर्याप्त सबूत है। इसलिए आरोपियों को जमानत नहीं दी जाए।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों से सहमत होकर मुख्य आरोपी जगदीश विश्नोई सहित, अन्य तीन आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि आठ महीने पहले जगदीश बिश्नोई को जैईएन भर्ती-2020 पेपर लीक मामले में जमानत मिली थी, लेकिन एसआई भर्ती मामले में जेल में बंद होने के चलते वह जेल से बाहर नहीं आ पाया था। ऐसे में अब याचिका खारिज होने के चलते उसे फिलहाल जेल में ही बंद रहना पड़ेगा।

राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ , तेलंगाना व आंध्र के दौरे पर

नयी दिल्ली 19 नवम्बर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से छत्तीसगढ़ , तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तीन दिन की यात्रा पर जायेंगी।

राष्ट्रपति सचिवालय ने बुधवार को बताया कि मुर्मू गुरुवार को अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी।

- वे आज अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातिय गौरव दिवस समारोह में शामिल होंगी।**

शुक्रवार को वह सिकंदराबाद के बोलारम स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगी। भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की समृद्ध सांस्कृतिक, पाककला और कलात्मक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
में होने हैं, तृणमूल कांग्रेस द्वारा कांग्रेस के लिए कोई जगह छोड़े जाने की संभावना कम ही है।

तमिलनाडु में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन भी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, खासकर इसलिए, क्योंकि कांग्रेस, अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी, टीवीके के कर्तब दिख रही है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पहले ही इंडिया ब्लॉक से बाहर होने की घोषणा कर चुके हैं, और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कांग्रेस से उचित दूरी बनाए रखने के संकेत दे रहे हैं।

कांग्रेस ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
हर कोशिश को उजागर करेंगे, चाहे वह कितनी ही सूक्ष्म क्यों न हो, जो असली मतदाताओं को हटाने या फर्जी मतदाताओं को जोड़ने के लिए की जा रही है। कांग्रेस पार्टी संस्थाओं के पक्षपातपूर्ण दुरुपयोग से लोकतांत्रिक सुरक्षा -तंत्र को कमजोर नहीं होने देगी।”

राजस्थान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नवंबर को तय की है।

याचिका में अधिवक्ता सविता सिहाग ने कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए। अगस्त 2023 को विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने आवेदन किया था।

याचिका में आरोप लगाया गया कि आवेदन करने समय प्रोफेसर अल्पना ने अपने ऊपर लंबित आपराधिक प्रकरण की जानकारी नहीं दी। जबकि नियमानुसार, उन्हें इस संबंध में जानकारी देनी थी। ऐसे में उन्होंने लथय छुपा कर नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में उनके चयन को निरस्त किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ में राज्य सरकार सहित, अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब पक्ष करते हुए स्ट्रे एप्लीकेशन पर प्रोफेसर अल्पना से अलग से जवाब देने को कहा है।

डॉ. शाहीन ने अल-फलाह की प्रयोगशाला से बम बनाने के रसायन चुराये

एनआईए ने डॉ. शाहीन द्वारा उपयोग की गई संदिग्ध कार कानपुर से बरामद की

नयी दिल्ली, 19 नवंबर। दिल्ली विस्फोट मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उत्तर प्रदेश के कानपुर के हितकारी नगर से हरियाणा में पंजीकृत एक संदिग्ध कार बरामद की है। एनआईए अधिकारी कार के मालिकाना हक की जांच कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में गिरफ्तार डॉ. शाहीन सईद विस्फोट से लगभग 25 दिन पहले कानपुर गयी थी। पृष्ठताछ में डॉ. शाहीन और उसके सहयोगी मुजम्मिल ने कथित रूप से फरीदाबाद स्थित अल-फ़लाह विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से बम बनाने के लिए रसायन चुराने की बात स्वीकार की। कई छापों के बाद

- एनआईए की जांच में जानकारी मिली है कि डॉ. उमर नबी कथित रूप से आत्मघाती हमलावरों की भर्ती व प्रशिक्षण की कोशिश कर रहा था। उसका उद्देश्य पूरा आत्मघाती दस्ता तैयार करना था।**

विश्वविद्यालय पहले ही जांच के दायरे में है। इस बीच, एनआईए की व्यापक आतंकवाद-रोधी जांच से पता चला है कि डॉ. उमर नबी कथित रूप से अतिरिक्त आत्मघाती हमलावरों की भर्ती एवं प्रशिक्षण की कोशिश कर रहा था। कार्रवाई में पाया कि उसने कम से कम 11 व्यक्तियों को प्रेक वीडियो वितरित किया था, जिनमें से सात कश्मीर से तथा

अन्य उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक से थे। उन सभी का विश्वविद्यालय से कोई न कोई संबंध था। एनआईए सूत्रों के अनुसार, उमर का उद्देश्य अकेले काम करने के बजाय, एक पूरा आत्मघाती दस्ता तैयार करने का था। फोरेंसिक टीमें उसके अंग्रेजी वीडियो के असामान्य लहजे की जांच कर रही हैं जो कृत्रिम रूप से संशोधित प्रतीत होता है।

